

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

नवभारत टाइम्स | नई दिल्ली | शुक्रवार, 26 जनवरी 2024

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
FRIDAY, JANUARY 26, 2024

रेहड़ी-पटरी वालों के खिलाफ कार्रवाई न करे पुलिस: HC



जी20 समिट के दौरान इस स्ट्रैच पर हुए कई डिवेलपमेंट के काम

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

धौला कुआं में गुड़गांव बस स्टैंड के पास रेहड़ी-पटरी लगाकर अपना और अपने परिवार का पेट पालने वाले दुकानदारों को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने ऐसे 17 फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई से दिल्ली पुलिस को रोक दिया है। जस्टिस विभू बाखरू और जस्टिस तारा वितस्ता गंजू की बेंच ने कहा कि पुलिस याचिकाकर्ताओं को ऐसे ही परेशान नहीं कर सकती है। जांच एजेंसी को मामले में स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने का अधिकार तभी है, जब लैड ऑफिंग एजेंसी या जमीन का मालिकाना हक रखने वाली एजेंसी उसे ऐसा करने के लिए कहे या अनुरोध करे। इस केस में कंटोनमेंट बोर्ड ने खुद कहा है कि इन्हें अपनी जगह पर लगने दिया जाए। फिर दिल्ली पुलिस को हक नहीं बनता है कि वह इन्हें वहां पर बैठने से मना करे। ऐसा एडवोकेट कमलेश कुमार मिश्र ने बताया, जिन्होंने सुरेंद्र कुमार समेत 17 वेंडर्स की ओर से याचिका दायर कर मामले में दखल देने का हाई कोर्ट

से अनुरोध किया।

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता मेट्रो पिलर नंबर-85 के पास धौला कुआं, गुड़गांव बस स्टैंड पर डीडीए की दीवार के पास खाली जमीन पर अपनी रेहड़ी-पटरी लगाते हैं। यह इलाका दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारक्षेत्र में आता है। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट-2014 की धारा 3(3) के अनुसार, इनका सर्वे हो चुका है और इन्हें वहां बैठने की मान्यता हासिल है। याचिकाकर्ताओं ने खासतौर पर इस बात को लेकर परेशानी जताई कि टाउन वेंडिंग कमिटी द्वारा इनके पक्ष में आदेश जारी करने के बावजूद दिल्ली पुलिस के अधिकारी इन्हें शांति से अपना काम करने नहीं दे रहे हैं। पुलिस

धौला कुआं में गुड़गांव बस स्टैंड के पास रेहड़ी-पटरी लगाने वालों को दी राहत

के रुख को देख अन्य विभागों के अधिकारी भी इन्हें परेशान करने लगे हैं, इसलिए इन्हें मदद के लिए अदालत में आना पड़ा। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड की टाउन वेंडिंग कमिटी की प्रस्तावना के बावजूद दिल्ली पुलिस के अधिकारी उन्हें रोजाना परेशान करते हैं और वहां से हटा देते हैं।

Delhi achieves 75% of total plantation target

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: The national capital has achieved 75% of its total plantation target this financial year. So far, a total of 79.7 lakh plants, trees, shrubs and hedges have been planted. The total annual plantation target for financial year 2023-24 was 1.2 crore, which also included over seven lakh for free distribution. The agencies will have to plant the rest before March-end.

According to a report by Delhi Pollution Control Committee on air pollution, till Nov 30, 2023, a total of 79.7 lakh plantations were done. Of this, 72.8 lakh were planted by coordinating agencies, including Delhi's forest depart-

ment, Municipal Corporation of Delhi, Public Works Department and Delhi Development Authority.

The report further stated that for dust control measures, a cell was constituted by 12 road-owning agencies, and greening of central verges was one of the targets set by the commission for air quality monitoring. It, however, added that out of the total central verge stretch of 1,936 km in Delhi, only about 3-km stretch is to be greened.

Over 40 species of native trees, 20 native species of shrubs, 13 species of climbers and 22 species of herb like satvari, khartua, bringraj, chickweed and Indian fumitory are being planted this year.

हिन्दुस्तान

नई दिल्ली, शुक्रवार, 26 जनवरी 2024

29 जनवरी तक फलैटों के लिए करें पंजीकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के लजरी फलैटों की ई-नीलामी का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इसके लिए 29 जनवरी शाम 6 बजे तक पास पंजीकरण करने का अवसर है। ई-नीलामी 5 फरवरी को शुरू होगी। ज्यादा जानकारी नंबर 1800110332 पर उपलब्ध है।

एनजीटी ने डीडीए-एसडीएम साकेत से पार्क को बचाने के लिए कहा

दिस, नई दिल्ली: एनजीटी ने डीडीए और साकेत के एसडीएम को निर्देश दिया कि वह सभ्य दिल्ली के एक पार्क को अतिक्रमण से बचाने के लिए मिलकर कार्रवाई करें। ट्रिब्यूनल एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आरोप लगाया गया कि पार्क, जिसे डीडीए

का ग्रैंड भी कहा जा सकता है, पर झुगियां बनाकर, कचरा जमा कर और डेयरी संबंधी गतिविधियों के जरिए बर्बाद किया जा रहा है। पिछले साल ट्रिब्यूनल ने निर्देश दिया था कि वे अतिक्रमण हटाकर आसपास फेंसिंग करें और पार्क पर पेड़-पौधे लगाकर उसे हरा भरा बनाएं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS हिन्दुस्तान DATED 27/01/2024

लेटलतीफी | दिल्ली सरकार ने 2022 में सड़क किनारे खाली जगहों पर चार्जिंग प्वाइंट लगाने की घोषणा की थी, लेकिन काम नहीं हुआ

राजधानी में ईवी चार्जिंग प्वाइंट लगाने का काम पिछड़ा

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन और निजी तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के बेड़े में शामिल हो रही बसों के लिए सरकार ने बस डिपो पर चार्जिंग प्वाइंट तैयार किए हैं, लेकिन निजी तौर पर खरीदे जा रहे वाहनों के लिए अभी तक सार्वजनिक चार्जिंग प्वाइंट और स्टेशन की संख्या सीमित है। इसका कारण है कि बीते कुछ महीनों के दौरान चार्जिंग स्टेशन और प्वाइंट बनाने का काम पिछड़ा है। घोषणा के बाद भी सड़क किनारे खाली जगहों पर चार्जिंग प्वाइंट लगाने का काम भी आगे नहीं बढ़ पाया है।

तीन किलोमीटर की परिधि में सुविधा देना लक्ष्य

इलेक्ट्रिक वाहनों की तेजी से बढ़ती संख्या के बीच अब सरकार के सामने असल चुनौती बेहतर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। इसी को ध्यान में रख सरकार ने तीन किलोमीटर की परिधि में एक चार्जिंग प्वाइंट तैयार करने का लक्ष्य रखा है। मार्च, 2022 में 2025 तक राजधानी के अंदर 18 हजार नए चार्जिंग प्वाइंट तैयार करने की योजना बनाई थी, लेकिन जमीनी स्तर पर तेजी से काम नहीं हो पाया है।

दिल्ली में चार्जिंग सुविधा

चार्जिंग स्टेशन	1919
चार्जिंग प्वाइंट	2452
बैटरी स्वैप स्टेशन	232



100

सड़कों के किनारे लगाए जाने हैं चार्जिंग प्वाइंट

18

हजार चार्जिंग प्वाइंट तैयार करने का लक्ष्य रखा है दिल्ली सरकार ने

अन्य एजेंसी भी चार्जिंग स्टेशन बनाने में पीछे

बीते वर्ष एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में भी लोकल सड़क, राज्य, नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के किनारे चार्जिंग स्टेशन तेजी से तैयार करने पर मंथन हुआ। पेट्रोलियम कंपनियों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, स्थानीय प्राधिकरण समेत अन्य एजेंसियों ने सहमति जताई कि अगले छह से सात माह में इस काम में तेजी आएगी, लेकिन कुछ हाईवे और एक्सप्रेसवे के किनारे पेट्रोल पंपों पर ही चार्जिंग प्वाइंट बनाए गए।

सितंबर, 2022 में दिल्ली सरकार ने सड़क किनारे खाली जगहों पर सिंगल चार्जिंग प्वाइंट लगाने की घोषणा की थी। इसके लिए लोक

निर्माण विभाग, एमसीडी, डीडीए समेत अन्य विभागों के साथ मिलकर रूप रेखा भी तैयारी की गई। सरकार ने पीडब्ल्यूडी की 100 सड़कों के

किनारे चार्जिंग प्वाइंट तैयार करने का लक्ष्य रखा था। मार्च, 2023 में सरकार ने पहले चरण के तहत पीडब्ल्यूडी विभाग की 60 सड़कों को

चिह्नित कर 100 चार्जिंग प्वाइंट तैयार करने की योजना बनाई थी, लेकिन उस दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हुई।

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2024

फिर से राजधानी के गांवों में रात्रि प्रवास करेंगे डीएम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: एलजी वीके सक्सेना द्वारा 'संवाद' के जरिए लोगों की शासन में भागीदारी, विशेष रूप से दिल्ली के गांवों के विकास कार्यों को तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित

करने के लिए की गई अनूठी पहल को जमीन पर लागू करने का सिलसिला जारी है। डीडीए के महत्वाकांक्षी 'दिल्ली ग्रामोदय अभियान' के तहत किए जाने वाले विकास कार्यों के बारे में ग्रामीणों के साथ 'संवाद' के माध्यम से अनुभव प्राप्त करने के लिए गांवों में रात भर रुकने की कवायद जारी रखते हुए, वरिष्ठ नोडल अधिकारी, डीएम, डीडीए, एमसीडी, डीजेवी और पीडब्ल्यूडी

आदि जैसे संबंधित एजेंसियों के सभी वरिष्ठ अधिकारी शनिवार और रविवार को सभी 11 जिलों के चिह्नित गांवों में रात बिताएंगे।

पिछली बार ग्रामीणों के फीडबैक से मिले अनुभव से अधिकारियों को 'दिल्ली ग्रामोदय अभियान' के तहत किए जाने वाले विशिष्ट कार्यक्रमों को तैयार करने में मदद मिली। इससे उत्साहित होकर उपराज्यपाल के निर्देशानुसार अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच यह दूसरा 'संवाद' होगा। इस अभ्यास का उद्देश्य 800 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से डीडीए द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे महत्वाकांक्षी 'दिल्ली ग्रामोदय अभियान' के तहत, ग्रामीणों के परामर्श से दिल्ली के गांवों के लिए विकास योजना तैयार करना है।

अपने दौरे की शुरुआत के पहले दिन, सभी डीएम सुबह 11 बजे तीन

11 जिलों के चयनित गांव

पश्चिमी	नीलवाल
उत्तर-पश्चिमी	मदनपुर डबास
दक्षिण-पश्चिमी	छावला
दक्षिण	भाटी
दक्षिण-पूर्वी	आली
पूर्वी	दल्लूपुरा
शाहदरा	सबोली
उत्तर पूर्वी	बदरपुरख़ादर
सैंदल	बुराडी
नई दिल्ली	रंगपुरी
उतरी	मुंगेशपुर

घंटे तक चयनित गांव और उसके आस पास के गांवों के लोगों से संवाद करेंगे। अपराह्न तीन से शाम छह बजे तक वे विभिन्न संबंधित विभागों, जिनमें डीडीए, राजस्व, डीजेबी और एमसीडी आदि शामिल हैं, के

सभी संबंधित अधिकारियों के साथ पिछले 'संवाद' के दौरान चिह्नित गए कार्यों के अनुसार निरीक्षण के लिए महत्वपूर्ण स्थलों का दौरा करेंगे। शाम छह से सात बजे तक, सभी ग्रामीणों के साथ 'नाइट फायर' पर एक 'चर्चा' आयोजित की जाएगी, जहां ग्रामीणों को अपनी शिकायतें और प्रतिक्रिया साझा करने के लिए कहा जाएगा। शनिवार और रविवार के बीच की मध्यरात्रि के विश्राम के बाद, डीएम चिह्नित गांव के विभिन्न स्थानों पर विकास के लिए अस्थायी रोडमैप साझा करने के लिए सुबह 7:00 बजे से 11:00 बजे के बीच 'संवाद' का दूसरा दौर शुरू करेंगे। मालूम हो कि उपराज्यपाल दो जनवरी को राजनिवास में संवाद का आयोजन कर 180 गांवों का प्रतिनिधित्व करने वाले 500 से अधिक ग्रामीणों के साथ बातचीत की थी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

हिन्दुस्तान

NAME OF NEWSPAPERS..... नई दिल्ली, शनिवार, 27 जनवरी 2024 - DATED.....

उम्मीद | दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लैंडपूलिंग नीति के तहत तीन जोन की योजना तैयार की, हर सेक्टर में ग्रामीण क्षेत्रों के जमीन मालिक और निजी बिल्डर मिलकर संघ बनाएंगे

इंफ्रा-मास्टर प्लान से देहात में भी विकास कार्य रफ्तार पकड़ेंगे

■ राहुल गान्ध
नई दिल्ली। लैंडपूलिंग नीति के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने तीन जोन का इंफ्रा-मास्टर प्लान तैयार किया है। इससे अब जोन में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों में तेजी आएगी।
डीडीए के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लैंडपूलिंग नीति में डीडीए ने छह जोन बनाए हैं। प्लान के तहत पी-1, पी-2 और एन जोन में सीवर नेटवर्क, पानी की व्यवस्था और टोस कचरा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण से जुड़ा डिजाइन तैयार किया गया है। तीनों जोन की आधारभूत संरचना (इंफ्रामस्ट्रक्चर) के मास्टर प्लान बनने से नीति को गति मिलेगी। साथ ही सभी जोन में संघ (कंसोर्टियम) के गठन की प्रक्रिया

में भी तेजी आएगी। अधिकारी ने बताया कि लैंडपूलिंग नीति के लिए संघ का गठित होना जरूरी है। जोन के हर सेक्टर में ग्रामीण क्षेत्रों के जमीन मालिक और निजी बिल्डर मिलकर संघ बनाएंगे। यह संघ ही डीडीए के साथ कानूनी रूप से सेक्टरों को विकसित करने के लिए योजना बनाएगा। पी-1, पी-2, एन, के-1, एल और जे जोन में कुल 138 सेक्टर बनाए गए हैं।
इनमें छह माह के अंदर संघ को गठित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक चार जोन के 16 सेक्टरों में संघ के गठित होने की प्रक्रिया जारी है। पी-1 के 7 सेक्टरों में, पी-2 के 8 सेक्टरों में, एन जोन के 1 सेक्टर में और एल के एक सेक्टर में अगले एक से दो माह में संघ के पूरी तरह से गठित होने की उम्मीद है।



एक माह में पंजीकरण शुरू
जोन के सेक्टरों में संघ के गठित करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया जा रहा है। संघ को गठित करने के लिए हितधारकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। एक माह में डीडीए की वेबसाइट में पंजीकरण शुरू हो जाएगा। दिल्ली में डीडीए के सभी जोनल कार्यालयों में अधिकारियों के साथ मिलकर संघ से जुड़े प्रतिनिधि बातचीत करेंगे। डीडीए ने 20 अधिकारियों को सभी जोन में तैनात किया है।

यहां के लिए प्लान बना
नरेला के मौजूदा विकसित इलाके से बाहर की जगह को पी-1 जोन में निर्धारित किया है। इस क्षेत्र को नरेला सब सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं, पी-2 जोन को उत्तरी दिल्ली में बनाया गया है। यह जोन बख्तावरपुर गांव से आसपास जाकर तिग्गीपुर और आसपास के क्षेत्र में निर्धारित किया गया है।

योजना को लागू करने में सहायक है संघ का गठन
डीडीए के अधिकारियों के अनुसार लैंडपूलिंग पॉलिसी को लागू करने के लिए संघ का गठन होना बेहद आवश्यक है। पॉलिसी के निर्धारित किए गए प्रत्येक जोन के अधीन आने वाले सेक्टरों के लिए एक-एक संघ का गठन होगा। यह संघ (कंसोर्टियम) डीडीए की निगरानी में सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मॉडल के अनुरूप उस जोन को विकसित करेगा।

गांवों में दो दिन रात्रि प्रवास करेंगे 11 जिलों के डीएम

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। राजधानी दिल्ली के चुने हुए गांवों में अगले दो दिन 11 जिलों के डीएम रात्रि प्रवास करेंगे। इस दौरान वे ग्रामीणों के साथ संवाद करने के साथ-साथ वे डीडीए द्वारा चलाए जा रहे दिल्ली ग्रामोदय अभियान की योजनाओं पर भी चर्चा करेंगे।
हाल ही दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के गांवों के विकास के लिए संवाद के जरिए लोगों की शासन में भागीदारी सुनिश्चित करने की महल की शुरुआत की थी। इस

क्रम में डीडीए की महत्वाकांक्षी दिल्ली ग्रामोदय अभियान को लेकर 11 जिलों के चुने हुए गांवों में शनिवार और रविवार को सभी वरिष्ठ अधिकारी रात्रि प्रवास करेंगे। इसमें वरिष्ठ नोडल अधिकारी, डीएम, डीडीए, नगर निगम, डीजेबी और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी शामिल हैं। राजनिवास के मुताबिक रात्रि प्रवास के लिए नीलवाल, मदनपुर डबास, छावला, बाटी, आली, दल्लपुरा, सबोली, बदरपुर खादर, बुराड़ी, रंगपुरी और मुंगेशपुर गांवों को चुना गया है।

29 जनवरी तक फ्लेटों के लिए करें पंजीकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के लग्जरी फ्लेटों की ई-नीलामी का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इसके लिए 29 जनवरी शाम 6 बजे तक पास पंजीकरण करने का अवसर है। ई-नीलामी 5 फरवरी को शुरू होगी। ज्यादा जानकारी नंबर 1800 110332 पर उपलब्ध है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण

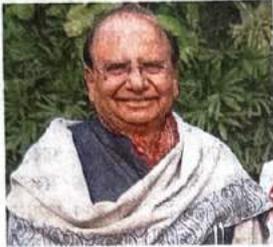
NAME OF NEWSPAPERS

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2024

DATED

दिल्ली को बना रहे वैश्विक और समावेशी शहर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: एलजी वीके सक्सेना ने शुक्रवार को अपने गणतंत्र दिवस भाषण में कहा कि केंद्र और स्थानीय सरकार दिल्ली को एक वैश्विक और समावेशी शहर के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। सक्सेना ने अपने भाषण में सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य, बिजली क्षेत्र और राशन आपूर्ति सहित दिल्ली की विभिन्न उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली ने बिजली क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। बिजली की मांग बिना किसी लोडशेडिंग के पूरी की जा रही है। सक्सेना ने लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामना दी और संविधान के निर्माताओं और देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।



एलजी वीके सक्सेना

- गणतंत्र दिवस के भाषण में एलजी ने गिनाई सार्वजनिक परिवहन, बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धियां
- बीते एक साल में दिल्ली को बदलने के लिए कई परियोजनाएं पूरी की गई हैं, दो विश्व स्तरीय सभागार तैयार हुए

कि 2025 तक दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन की 85 प्रतिशत बसें इलेक्ट्रिक होंगी। वैश्विक स्तर पर यह एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा, केंद्र ने फेम (फास्टर एडापशन एंड मैनुफैक्चरिंग आफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) योजना के तहत विशेष वित्तीय सहायता दी है।

उपराज्यपाल ने कहा कि समावेशी विकास के लक्ष्य के साथ समाज के सभी वर्गों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और 72 लाख लाभार्थियों को उचित मूल्य की दुकानों से सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा, 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' लाभार्थियों की संख्या (देश में) सबसे ज्यादा है। सरकार वायु और

लोकतंत्र को मजबूत करने का संकल्प लें: अरविंद केजरीवाल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस पर लोगों से संविधान की रक्षा की शपथ लेने का आह्वान किया। केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 75वें गणतंत्र दिवस पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर अपने संविधान की रक्षा करने और अपने महान लोकतंत्र को मजबूत करने की शपथ लें। भारत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाता है क्योंकि इसी दिन 1950 में इसका संविधान लागू हुआ था।



अरविंद केजरीवाल

जल प्रदूषण से निपटने और यमुना नदी के संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध है। एमसीडी भी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों के प्रभावी और समय पर कार्यान्वयन के लिए प्रयास कर रहा है। पिछले एक साल में दिल्ली को बदलने के लिए कई परियोजनाएं पूरी की गई हैं। उन्होंने कहा, दो विश्व स्तरीय सभागारों- भारत मंडपम और यशोभूमि- का उद्घाटन किया गया है और मेरठ और दिल्ली के बीच क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) शुरू हो गया है और दिल्ली-अलवर और दिल्ली-पानीपत कारिडोर पर काम प्रगति पर है।

डेढ़ वर्ष पूर्व धंसी सड़क की नहीं हुई मरम्मत, इनोवा और वैगनआर भिड़ीं



रोहिणी सेक्टर-23 व 24 की सड़क पर गड़दा • जागरण

जासं, बाहरी दिल्ली: रोहिणी सेक्टर-23-24 की डिवाइडिंग रोड पर शुक्रवार की सुबह इनोवा व वैगनआर के बीच आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिससे दोनों ही वाहन क्षतिग्रस्त हो गईं। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। पुलिस ने दोनों वाहन चालकों के बयान के आधार पर जांच शुरू कर दी है। डेढ़ वर्ष पहले यहां सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंसने से 300 मीटर तक यह सड़क वनवे है। डीडीए की यह सड़क अभी तक नहीं बनाई गई है। वाहन चालक यहां विपरीत दिशा में आने के लिए मजबूर हैं, जो हादसे का कारण बन रहे हैं। इस रोड की खबर प्रकाशित कर जागरण ने पहले भी संबंधित विभाग को अवगत कराया था। समय रहते संबंधित विभाग के अधिकारी ने इसपर ध्यान नहीं दिया, जिससे हादसा हो गया। स्थानीय लोग लगातार संबंधित डीडीए अधिकारियों से सड़क बनाने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के सुस्त रवैये का नतीजा है कि यह सड़क अभी तक नहीं बन पाई है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NEW DELHI
SATURDAY

NAME OF NEWSPAPER **Hindustan Times** JANUARY 27, 2024

NGT orders removal of squatters from a green patch in Lado Sarai

LG HAILS DELHI'S ACHIEVEMENTS IN PUBLIC TRANSPORT, INFRASTRUCTURE

HT Correspondent

letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Lieutenant governor VK Saxena, in his Republic Day speech on Friday at the LG secretariat, hailed Delhi's civic agencies and the Delhi Police and said that the central and local governments were making sustained efforts to develop Delhi as a global and inclusive city.

Highlighting the achievements in the fields of public transport, health, power and ration supply, Saxena said that many projects have been completed in the national capital.

He attributed the success of the G20 Summit held in September to the unified efforts of various agencies including DDA, PWD, NDMC, MCD, and Delhi Police, among others, apart from the workers. "Two world-class auditoriums — Bharat Mandapam and Yashobhoomi — have been inaugurated and the RRTS between Meerut and Delhi has begun. Besides, the work is already in progress on the Delhi-Alwar and Delhi-Panipat corridors," he said.

He added that the government was committed to giving top priority to health services and making them available to the people. "The Centre has extended special financial assistance under the FAME scheme and efforts are being made for inclusive development of the society here," he added.

Saxena also said that after the unification of MCD, various public welfare schemes and development works were on track for systematic and time-bound implementation.

boundary walls, according to documents seen by HT.

The land, which comes under DDA's jurisdiction, includes a forest patch and a park, which was encroached upon by jhuggis and was being used to illegally dump waste, the tribunal said, adding that even illegal dairies had cropped up in the area. NGT's directions came following a

report submitted by a joint committee last August, which noted the allegations by locals regarding the encroachments were true.

"During the visit, it was observed that there was a park on DDA land. Information boards of DDA were also found wherein it was mentioned that encroachment and dumping are illegal on DDA land. It was

observed that people had occupied the DDA (land) and built their temporary houses. Some cows and buffaloes were also seen," the committee, comprising the Delhi Pollution Control Committee (DPCC) and SDM (Saket) informed the tribunal.

HT reached out to DDA, but did not get any response on request for comments.

SENIOR OFFICIALS TO STAY IN CITY VILLAGES UNDER NEW DDA PLAN

NEW DELHI: Aiming at participatory governance by engaging with the people through dialogue, the district magistrates (DMs) of all the 11 districts will stay overnight in selected villages on Saturday and Sunday, officials aware of the matter said on Friday.

The officials will chalk out restoration and development plans for Delhi's villages, in consultation with the villagers, under the ambitious "Dilli Gramoday Abhiyan". The project is being executed by the Delhi Development Authority (DDA) at a cost of over ₹800 crore," said a senior official of the lieutenant governor secretariat, who did not want to be named.

Officials said that this will be for the second time that the DMs will stay overnight at selected villages, after LG VK Saxena's order was issued on January 2.

HT Correspondent

letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The National Green Tribunal (NGT) has given the Delhi Development Authority (DDA) and the subdivisional magistrate (Saket) three months to remove all encroachments from a piece of land in Lado Sarai and secure it by building

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
SATURDAY, JANUARY 27, 2024

Joint Effort Helped Transform Delhi's Landscape In 2023: LG

Cites Successful Hosting Of G20 Summit, Achievements In Edu, Health

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Lieutenant governor VK Saxena on Friday said Delhi achieved significant milestones in 2023 and central and state governments were making "sustained efforts" to develop the capital into a global and inclusive city.

In his speech on the Republic Day, the LG also appreciated the efforts made by various central and state government agencies in the "successful" hosting of the G20 summit last year. Highlighting various achievements made in the fields of public transport, health, power sector and ration supply, Saxena said several projects executed in the past year transformed the landscape of Delhi.

"The inauguration of two world-class convention centres — Bharat Mandapam and Yashobhoomi — by the central government and the initiation of the RRTS (rapid rail transit system) on the Delhi-Meerut and Delhi-Panipat lines signify the progress made in the capital," the LG said.

He emphasised that Delhi

government managed to modernise its public transportation system as per the needs of the city and converted 80% of the city bus fleet into electric with the financial assistance from the central government under FAME-II scheme would mark a significant global achievement.

"We are committed to addressing air and water pollution and working towards conserving the Yamuna," Saxena said, adding that the eastern and western peripheral expressways significantly helped in addressing traffic congestion and pollution issues in the capital. Urban Extension Road-II, connecting NH-44 and NH-48, will be ready soon, the LG stated.

The LG said Delhi made remarkable progress in the power sector ensuring uninterrupted electricity supply.

"Delhi's economic foundation is also robust, with per capita income approximately 2.6 times higher than the national average. The service sector contributes nearly 85% to the economy, showcasing the strength of Delhi's economy," Saxena remarked.



Anindya Chattopadhyay

EYES ON THE SKIES: R-Day spectacle enthralled audience

The LG further said the civic bodies were working efficiently to implement various welfare schemes and development projects in a timely manner. He added that several projects such as multilevel car parking and improvement in schools were under way.

Saxena also appreciated the efforts made by DDA to provide housing to slum dwellers and said after the in situ rehabilitation project at Kal-

kaji, the EWS flats in Jailorwala Bagh and Kathputli Colony were also ready. He added that DDA undertook significant work for the rejuvenation of the Yamuna and transformed construction and demolition waste dump sites into beautiful tourist destinations such as Baansera and Asita.

The LG added that DDA was also developing Vasudev Ghat apart from Delhi Chalo Park, Urdu Academy Park,

Ghata Masjid Park and 'Sadbhavana Park'.

Talking about the efforts made to improve law and order in the capital, the LG said that Delhi Police effectively incorporated technology into its operations and ensured strategic deployment of personnel at hotspots using crime mapping system.

"Delhi Police has become the first in the country to use blockchain technology. This enables secure transmission of forensic evidence through QR codes to the FSL for analysis," said Saxena.

He added that for the security of the vulnerable groups, Delhi Police has established 24x7 women help desks at all police stations and developed Himmat-Plus app for women in distress.

"Delhi Police is committed and dedicated to address every aspect of law enforcement and security. Crime is a social problem and the cooperation of the community, that is, all residents of Delhi, will be necessary to address it," the LG said in his address to people.

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
SATURDAY, JANUARY 27, 2024

NGT gives 3 months to free land of encroachment at Lado Sarai

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: The National Green Tribunal (NGT) has given three months' time to Delhi Development Authority (DDA) and the sub divisional magistrate (Saket) to remove encroachment from a piece of land in Lado Sarai and file an action taken report.

An NGT-appointed joint committee, Delhi Pollution Control Committee and SDM (Saket) had informed the tribunal earlier that some people had occupied land, which in-

cluded a park, in Lado Sarai and built jhuggis on it. The panel also found cattle on the land, which comes under DDA.

The committee's report, filed with the tribunal in August last year, said the boundary walls of the park were found to be broken, which may be providing access to encroachers. "Garbage dumping and parking of vehicles were also observed on DDA land during the visit," said the report.

The bench headed by Justice Prakash Shrivastava said, "As per the said report, the-

re is garbage dumping on DDA land. The SDM Saket has submitted that DDA is required to take action for clearing garbage dumping and to ensure that no dairy activity or keeping of buffaloes and cows is done on that land."

The plea was filed by Saurobh Sejwal, a resident, who had alleged the area had been encroached on by illegal dairies. Sejwal had alleged that despite authorities demolishing illegal constructions in the area, encroachers kept returning and rebuilding again.

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
SATURDAY, JANUARY 27, 2024

SE Delhi's Baansera to get cafe soon, convention centre also on the cards

Vibha.Sharma@timesgroup.com

New Delhi: Delhi Development Authority (DDA) has completed work on its cafe project at Baansera in Sarai Kale Khan. In line with the theme of this park, Cafe Bamboo Oasis has been made in an eco-friendly manner. It has an indoor seating capacity of around 100 people as well as ample seating space outdoors.

DDA has recently initiated a process for leasing out the place on licence fee basis and the cafe is likely to become operational by next month when the place will be blooming with varieties of seasonal flowers, including tulips. With around 20,000 tulip plants, the park will be a feast for the eyes. "On Jan 22, we commenced the registration process, which will continue till Feb 17. The e-auctioning of Cafe Bamboo Oasis will be done on Feb 20," said a DDA official.

The cafe is being constructed with a temporary light-



Baansera has an indoor seating capacity of around 100 people

weight structure in mild steel with polyurethane foam roof panels. "To make the surface look attractive, there will be wooden flooring. People can soak up in the sun and enjoy the green space in the middle of the city at Baansera," said the DDA official further.

Besides the cafe, there is also a plan to construct a convention centre at the park and

designing for this has been done by NBCC. "It is still in the initial stage. The centre is likely to be spread over an area of 3,000 square feet. We are expecting this to be completed by next year," said the official.

The centre, which will be made entirely with bamboo, will be air-conditioned and will comprise a meeting hall and an interpretation room,

among other rooms. The estimated cost of the project is Rs 2.1 crore, according to sources.

The information for these facilities was first shared by lieutenant governor VK Saxena in Sept when he came to inaugurate a musical fountain installed in a waterbody at Baansera. The musical fountain operates in two slots — each for half an hour, on all days of the week, except Monday. The first show starts at 7.30pm and the second at 8.30pm. People can visit the place after paying a nominal fee of Rs 50. Entry is free for children up to 10 years and schoolchildren accompanied by parents, teachers and guardians.

"We are expecting a major increase in footfall when the cafeteria is made fully operational. The visitors will have ample space to sit, relax and watch the musical fountain," said the official.

Baansera is the city's first bamboo-themed park on the Yamuna riverfront.

DMs to again visit one village each, take feedback on work

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: District magistrates of 11 districts in the capital will again visit one village each in their jurisdiction on Saturday and interact with the residents to take their feedback on development works to be undertaken under Delhi Development Authority's ambitious 'Dilli Gramodaya Abhiyan'.

Raj Niwas officials said continuing with the exercise of visiting villages to get a first-hand experience through "samvaad" (dialogue) with the villagers, DMs, nodal officers, and senior officers from stakeholder departments — DDA, MCD, DJB and PWD — will stay overnight at the villages on Jan 27 and 28.

"The experience last time had proven to be extremely enriching with the feedback from villagers helping the officials to chalk out specific programmes to be undertaken under the 'Dilli Gramodaya Abhiyan'. Encouraged by the success thereof, this will be the second 'samvaad' between officials and the villagers, as desired by the lieutenant governor," said an official.

Following lieutenant governor VK Saxena's announce-

AN OFFICIAL SAYS

The experience last time had proven to be extremely enriching with the feedback from villagers helping the officials to chalk out specific programmes

ment on Jan 2 after the 'Samvaad @ Raj Niwas' programme, DMs had spent Jan 7 and 8 in villages in their districts.

"This is LG's novel initiative towards participatory governance by engaging with the people through dialogue for formulating and implementing developmental works," said an official.

The selected villages include Neelwal in west district, Madanpur Dabas in north-west, Chhawla in south-west, Bhati in south, Aali in south-east, Dallupura in east, Saboli in Shahdara, Badarpur Khadar in north-east, Burari in central, Rangpuri in New Delhi and Mugheshpur in north.

The DMs' stay will start on Saturday at 11am when they will have a three-hour long in-

teraction with the villagers. Between 3pm and 6pm, the officials will visit important sites for inspection as per the works identified earlier, followed by an hour-long 'charcha' with the residents by night fire to share their grievances and feedback.

On Sunday, the officials will have another dialogue with the residents between 7am and 11am to share the tentative roadmap for the villages' development.

The 'Samvaad @ Raj Niwas' was first of its kind interaction of LG with the villagers aimed at seeking suggestions to chalk out a comprehensive plan of action for development of Delhi's villages. The dialogue made villagers a key stakeholder in the development of urbanised and rural villages.

"Saxena, who has already adopted five villages — Qutabgarh, Jaunti, Daurala, Rawta and Nizampur — has envisaged developing other villages on similar lines. He had exhorted the villagers to identify the specific problems concerning their villages and the tentative solutions so that they could be incorporated while finalizing the plan of action for each village," said an official.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

नवभारत टाइम्स | नई दिल्ली | शनिवार, 27 जनवरी 2024

NAME OF NEWSPAPERS

कुरैनी में पार्क की हालत खराब, लोगों ने बनाई दूरियां

■ एनबीटी न्यूज, कुरैनी : नरेला के कुरैनी स्थित डीडीए के पार्क की हालत खराब है। यहां लोगों के लिए सुविधाओं की कमी है। ऐसे में इलाके के लोगों का कहना है कि पार्क में न तो हरियाली बची है और न ही लोगों के पैदल चलने के लिए फुटपाथ है। पार्क का गेट भी टूटा हुआ

है, रात होते ही पार्क अंधेरे में डूब जाता है। यहां लगी स्ट्रीट लाइट खराब है। लोगों के बैठने के लिए बेंच तक नहीं है। यहां पार्क में पहले की तरह लोग नहीं पहुंचते हैं। स्थानीय बच्चे सिर्फ यहां पर क्रिकेट खेलते हुए

लोगों का आरोप-करते रहते हैं शिकायत, लेकिन डीडीए अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान

दिखाई देते हैं। पार्क में लगे झूले टूट चुके हैं। बाउंड्री भी टूटी हुई है।

स्थानीय निवासी मनोज ने बताया कि इस पार्क की मेंटेनेंस को लेकर के कई बार स्थानीय लोगों ने

डीडीए से शिकायत की है, लेकिन अब तक विभाग के तरफ से ध्यान नहीं दिया गया। पार्क में गार्ड न होने से बड़ी संख्या में यहां असामाजिक तत्व मौजूद रहते हैं। पार्क में घूमने आए सोनू ने बताया कि पार्क के साथ ही कूड़े का ढेर पड़ा रहता है। पार्क के बाहर बने नाले का स्लैब टूटा हुआ है।

NGT ने वन विभाग से मांगा जवाब

■ विस, नई दिल्ली : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पेड़ों की कटाई के खिलाफ दायर नाहरपुर गांव के लोगों की याचिका पर दिल्ली के वन विभाग से जवाब मांगा है। लोगों ने पेड़ों के कटने से ग्रीन बेल्ट को नाहरपुर के नुकसान पहुंचने का दावा किया है। लोगों ने पेड़ काटने की

एनजीटी अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव की अगुवाई वाली बेंच ने वन विभाग और डीडीए को नोटिस जारी किए और मामले में 5 फरवरी को अगली सुनवाई से कम से कम एक हफ्ते पहले जवाब देने के लिए कहा। नाहरपुर आरडब्ल्यूए ने मामले में याचिका दायर की और आरोप लगाया कि रोहिणी के सेक्टर-7 में बसे नाहरपुर गांव के आसपास हरित पट्टी यानी ग्रीन बेल्ट है, जिसे पेड़ों की कथित तौर पर अवैध तरीके से कटाई के जरिए नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आवेदक के वकील ने दलील दी कि यहां लगभग 500 पेड़ हैं और उन सभी के काटे जाने का खतरा है।

आज और कल फिर गांवों में रुकेंगे अधिकारी

■ विस, नई दिल्ली: एलजी की तरफ से शुरू किए गए 'दिल्ली ग्रामोदय अभियान' के तहत सभी जिलों के डीएम इस वीकेंड फिर से दिल्ली के अलग-अलग गांवों में रात बिताएंगे और ग्रामीणों से संवाद कर उनकी दिक्कतों का पता लगाएंगे। साथ ही लोगों से मिले सुझावों के आधार पर ग्राम विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे।

राजनिवास से मिली जानकारी के अनुसार, उप राज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर दिल्ली में गांवों में विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाने और गांव के लोगों से बातचीत करके ग्रामीण विकास की परियोजनाएं बनाने के लिए इसी मंहीने 7 और 8 जनवरी को भी सभी जिलों के डीएम 'संवाद' कार्यक्रम के तहत गांवों में पहुंचेंगे। इसे काफी सराहना मिली थी, क्योंकि पहली बार स्थानीय प्रशासन में सर्वोच्च स्तर के अधिकारियों ने लोगों से उनकी समस्याएं जानी थीं। अब 27 और 28 जनवरी को एक बार फिर दिल्ली के सभी 11 जिलों के डीएम चयनित गांवों का दौरा करेंगे और रातभर वहां रुकेंगे। अपने ग्राम प्रवास के दौरान डीएम गांव और उसके पड़ोस के गांव में रहने वाले ग्रामीणों से संवाद करेंगे। डीएम के अलावा डीडीए, एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS

SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI
JANUARY 28, 2024

DATED

Sewage, poor plantation mar Vasant Kunj park, NGT told

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: The forest department's survey of a South Delhi park has found several issues such as untreated water being filled in the natural pond, damage to the fauna and flora, poor plantation, geotagging the trees, among others.

The inspection was done following NGTs order after a Vasant Kunj resident approached the tribunal in Sept 2022, regarding poor condition of Smriti Van, spread over 37 acres, with a large waterbody (machli talab).

The complainant said that Smriti Van was being used to hold fairs, political and religious ceremonies which create nuisance and disturb the neighbouring residents. Asserting that the park ought to be maintained in its pristine glory being the habitat of rare flora and fauna, the resident said that it was instead left without maintenance and has a very few trees. The resident alleged that a concretised artificial pond was also prepared for religious ceremonies.

Following this, NGT asked concerned officials from Delhi Development Authority (DDA) and the forest department to work towards proper maintenance of the lake at Smriti Van, plantation and removal of encroachment.

The forest department submitted a report to NGT following a series of inspections, including the one done in presence of DDA officials on Jan 17.

Suggesting a slew of measures, including compensatory plantation, utilisation of STP water, maintenance of ponds, eco-friendly amenities, geotagging the plants and recognising more areas for plantation, the report stated that while some plantation was done and eco-friendly perforated tiles being used, many issues were yet to be fixed.

"It was noted that the STP was non-functional, leading to the disposal of untreated

water into Machli Talab...adversely impacting the aquatic ecosystem. Issue includes a foul smell, black watercolour, and odour in Machli Talab. Clear separation of stormwater drains, and sewer line has not been implemented," stated the forest department's Jan 25 report, published on NGT's website on Saturday.

"This untreated water proved unsuitable for irrigating the saplings planted for compensatory plantation, resulting in adverse effects," the report said, adding that census and geotagging of existing trees was pending, and a compensatory plantation of 1750 saplings by NBCC not being maintained properly.

"Adequate area is available for further compensatory plantation, but as of now, no action has been taken. Currently, tree guards are rudimentary and susceptible to termite attacks...Grazing by Nilgai and goats is affecting the plantation due to shortage of tree guards," it stated, adding that the climate till Jan 29 was not suitable for plantation.

The forest department also stated the encroachment removal pertains to DDA and suggested to "Declare Smriti Van as a no plastic zone", allow only pedestrians, and promote native trees and plants.

हिन्दुस्तान

नई दिल्ली
रविवार

28 जनवरी 2024

फ्लैट को लेकर डीडीए के
कॉल सेंटर पर कॉल करें

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की पहले आओ पहले पाओ आवासीय योजना में फ्लैटों की बुकिंग व पंजीकरण प्रक्रिया जारी है। बुकिंग से जुड़ी दिक्कतों के बारे में आवेदनकर्ता सूचना दे सकते हैं। इसके लिए डीडीए कॉल सेंटर के नंबर 1800110332 पर कॉल कर सकते हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAM

* SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI
JANUARY 28, 2024

Four parks in Walled City all set to get a makeover

WHAT'S IN STORE

DDA has proposed redevelopment of the green area near Red Fort and parks along Mahatma Gandhi Marg

Parks in focus



Urdu Academy Park | 2.1 acres

Ghata Masjid Park | 7.4 acres

Spread over 37.5 acres

Dilli Chalo Park | 17 acres

Sadbhavna Park | 10.8 acres

Proposed



Dilli Chalo Park

Vibha.Sharma@timesgroup.com

New Delhi: Delhi Development Authority plans a complete redevelopment of the green space at the rear of Red Fort and nearby parks in the Walled City, including the Dilli Chalo, Ghata Masjid, Urdu Academy and Sadbhavna parks. Work on this will begin in Feb and finish in phases, beginning June.

The details of the project were discussed at a recent meeting chaired by lieutenant governor VK Saxena, also the chairman of DDA. "The project of redeveloping the four parks on Mahatma Gandhi Marg is in line with that of Kartavya Path and aims to provide similar recreational opportunities for the public. The LG has been monitoring the project regularly," a DDA statement said.

A DDA official said, "CPWD transferred these parks to us recently and we will upgrade these public spaces. The new designs are ready and tendering for the work is under way. Regarding the area at the rear of Red Fort, we have sought permission to initiate work from the Archaeological Survey of India, to whom it belongs."

To begin with, the plan for Dilli Chalo Park at the Red Fort's rear is in the Mughal Charbagh style. "Taking into

account the existing vegetation, the design keeps a formal axis focusing on various built elements of Red Fort," DDA said. "There will be fountains, pools and channels along the central axis and plantation of low floral species to add colour and variety with sufficient sitting spaces. An amphitheatre is positioned to emphasise one of the burjis of the historic fort."

The details of the project were discussed at a recent meeting chaired by LG VK Saxena, also the chairman of DDA

The materials proposed to be used in the revamp are red sandstone with occasional motifs in Dholpur stone or marble and handmade tiles for lining waterbodies. The project also includes providing decorative lighting. The two existing structures at the extremities of the park, presently housing public facilities, are proposed to be turned into food kiosks and their spillover spaces and parking areas revamped. The service road abutting the park will be redesigned to create parking space and vendor zones near the three proposed entrances.

"Two public toilets are conveniently located near the entry points and along the bounda-

Revamp to be done in phases

> Designs have been prepared and work will begin in February

> Dilli Chalo Park, located near Red Fort, to be developed in Mughal Charbagh style

> Water fountains and channels along the central axis and floral plantations will be the highlights

> Plan is to use red sandstone with some motifs in Dholpur or marble, handmade tiles for lining of waterbodies

> Sadbhavna Park will have a grand feature — Apollo's fountain with horses — as the centrepiece

> Ghata Masjid and Urdu Academy parks to be redeveloped as neighborhood parks



ry wall in such a manner that rentals for advertisements can be explored," said the official.

At Sadbhavna Park, the design envisages a French landscape, with a grand water feature resembling the Palace of Versailles' Apollo's fountain with its group of energetic horses as the focal element. An amphitheatre and a court with food trucks will mark the terminals of the central axis. "The design has simple linear laws acting as foreground to the grand water feature with tree-lined avenues to give perspective and symmetry. We propose to use marble with a dash of kota here," said the official.

As far as the Ghata Masjid and Urdu Academy parks are concerned, DDA will redesign them as neighbourhood green spaces to meet the requirements of the nearby residential area. "The key features of the place would be two seating pavilions, sculpture terraces, a shaded senior citizen plaza, children's play area, yoga lawn, multipurpose playground, open gym and public facilities. The abutting service road will be reworked to create ample parking space and vendor zones," revealed the official.

The materials proposed to be used here are murrum, grit finish and pavers with the green areas divided into lawns and low maintenance plantation zones.

सोसायटीज खुद भी बना रहीं रीडिगवेलपमेंट प्लान लेकिन...

विभाग कर देते हैं रिजेक्ट, अथॉरिटीज से प्लान बनाकर देने की मांग

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली के पुराने इलाकों का रीडिगवेलपमेंट करने की बात आम लोगों साथ विभिन्न अथॉरिटी भी समय समय पर कर चुकी है। लेकिन आईपी एक्सटेंशन को कुछ कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटीयां अपना रीडिगवेलपमेंट प्लान तैयार कर इसकी पहल भी चुकी है। यह अलग बात है कि विभागों ने इस प्लान को खारिज कर दिया। सोसायटीयों के अनुसार यदि इन सोसायटीयों को रीडिगवेलपमेंट प्लान बनाया तो दिल्ली की कई समस्याएं हल हो सकती हैं। सोसायटीयों के रीडिगवेलपमेंट प्लान क्या है आइए देखते हैं।

आईपी एक्सटेंशन में 118 के करीब कोऑपरेटिव सोसायटीज हैं। यह सभी 25 से 35 साल पुरानी हो चुकी है। उस समय की जरूरत व प्लानिंग के समय में बनी यह सोसायटीयां आज के समय की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रही हैं। सोसायटीयों की इसी कमी की वजह से ट्रैफिक जाम, अतिक्रमण, पानी, प्रदूषण, सौकरेज आदि की समस्या राजधानी में विकरल हो रही है।



Surender Kumar



NBT
कायापलट
घर वही, सूरत नई

■ 70 के दशक में बनी आईपी एक्सटेंशन की कोऑपरेटिव सोसायटीयों ने भी बनाया है अपनी खुद का रीडिगवेलपमेंट प्लान

ये है रीडिगवेलपमेंट प्लान

ग्रीन बिल्डिंग बनेगी

रीडिगवेलपमेंट के तहत दिए गए विकल्प सोसायटी के प्लान में बताया गया था कि यह सोसायटीयों पूरी तरह ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर होंगी। यानी सूरज की रोशनी का अत्यधिक इस्तेमाल किया जाएगा इससे बिजली की कम जरूरत पड़ेगी। साथ ही सोसायटीयों की छतों पर रूफ टॉप सोलर पावर प्लॉट लगाए जाएंगे। जिससे हर सोसायटी अपनी बिजली खुद पैदा करेगी और अतिरिक्त बिजली सरकार को बेचेगी।

खुद का सीवेज ट्रीटमेंट

सीवेज और वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट भी इन सोसायटीयों में लगाए जाएंगे। अपना सीवेज यह सोसायटी खुद ट्रीट करेगी और फिर उसका इस्तेमाल फलस, बागवानी और गाड़ियों को धोने जैसे कामों में किया जाएगा। इसके लिए हर फ्लैट को दोहरे वॉटर कनेक्शन दिए जाएंगे एक डीजेबी और दूसरा ट्रीटड पानी का।

ज्यादा पार्किंग स्पेस

बेसमेंट में नए नियमों के मुताबिक तीन लेवल की पार्किंग बनाई जाएगी। इनसे सोसायटीयों को पार्किंग की जगह मिलेगी और उन्हें सोसायटी के बाहर गाड़ी खड़ी करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसकी वजह से सड़कों का पूरा इस्तेमाल ट्रैफिक के लिए हो सकेगा और जाम की समस्या का खतमा होगा।

अंदर ही दुकानें

हर सोसायटी में तीन से चार दुकानें होंगी। इसकी वजह से सोसायटी के अंदर ही लोगों को उनकी जरूरतें का सामान मिल सकेगा। इससे उनकी



सड़कों पर रेहड़ी लगाने वालों पर निर्भरता कम होगी। जब डिमांड कम होगी तो सड़कों से अतिक्रमण अपने आप हट जाएगा।

मिलेंगे बड़े प्लैट

इसके अलावा लोगों की बड़ी जरूरतों के हिसाब से बड़े प्लैट मिलेंगे। वर्किंग कपल को देखते हुए सोसायटीयों में हॉस्टल की तर्ज पर कॉमन किचन और लॉन्ड्री की सुविधा भी रहेगी। कम्युनिटी सेंटर, बैंक एटीएम, मेडिकल स्टोर आदि की सुविधा के साथ सर्विस लिफ्ट भी मिलेगी।

ग्रीन एरिया बढ़ेगा

साथ ही हर सोसायटी में ग्राउंड कवरेज एरिया को कम करके उसे अतिरिक्त एफएआर में इस्तेमाल किया जाएगा। इससे ग्रीन एरिया के साथ पार्क व प्लेग्राउंड की जगह भी बनेगी। हर सोसायटी में कम से कम 20 प्रतिशत अतिरिक्त प्लैट्स बनेंगे। सेप्टी सिवियरिटी के अच्छे इंतजाम होंगे।

हमने आईपी एक्सटेंशन की विकल्प सोसायटी को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना था। प्रपोजल बनाकर एमसीडी को सबमिट किया था। डीडीए ने इसे खारिज कर दिया। तो अब डीडीए ही रास्ता बता दे कि कोऑपरेटिव सोसायटीयों का रीडिगवेलपमेंट आखिर होगा कैसे?

- मदन खत्री, विकल्प सोसायटी

हम सभी प्रयास करके थक चुके हैं। हमारा प्लान अप्रूव नहीं होता और डीडीए कोई स्पष्ट प्लान हमें देता नहीं। सोसायटीयों की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। समस्या का जल्द समाधान निकालने की जरूरत है। - सुरेश जिंदल, संस्थापक, आईपी ग्रुप हाउसिंग सोसायटी महासंघ



सवालों के जवाब भी

अगर रीडिगवेलपमेंट को लेकर मन में कोई सवाल है तो उनका जवाब भी हम एक्सपर्ट्स की मदद से देंगे। रीडिगवेलपमेंट पर अपनी राय, सुझाव और सवाल आप ईमेल भी कर सकते हैं। अपना नाम, मोबाइल नंबर और अपने बारे में जरूरी जानकारी nbtreader@timesgroup.com पर भेज दें। सर्वेक्ट में Redevelopment जरूर लिखें।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS—

Hindustan Times

NEW DELHI
MONDAY
JANUARY 29, 2024

83 parks may be connected with sewage treatment plants

HT Correspondent

letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi Pollution Control Committee (DPCC) has been asked to create a network plan in consultation with the Delhi Jal Board (DJB) and the Delhi Development Authority (DDA) to connect 83 parks with existing sewage treatment plants (STPs), officials aware of the development have said.

The decision was taken on a

January 10 meeting of the high-level committee (HLC) on the Yamuna — the latest meeting of the panel — officials said, after DDA said these 83 parks were still functioning on borewells — the usage of which has been banned by the National Green Tribunal (NGT).

A DPCC official said the HLC has asked them to make use of Geospatial Delhi Limited (GSDL) — a company that maintains and updates spatial data through mapping and sur-

THE DECISION WAS TAKEN ON A JAN 10 MEETING OF THE HLC, AFTER DDA SAID THESE PARKS WERE STILL FUNCTIONING ON BOREWELLS

veys — to prepare the plan, based on which pipelines can be laid to connect parks to the

nearest STP.

"DDA has already shared a list of the parks, and now GSDL will be used to map out a network and the approximate distance to each STP. GSDL can also tell us the existing pipelines on the map," said the official.

Data shared during the latest meeting of the HLC shows that of the 565 million gallons per day (mgd) of treated waste water in Delhi, 267mgd is mandatorily being released in

the Yamuna, with 125mgd being put to use for horticulture purposes and for the revival of lakes and water bodies. Another 100mgd has been proposed to recharge the groundwater table in places, and to use it to revive Bhalswa Lake.

DJB said even after this, a gap of 73mgd existed.

"It has been decided to use this 73mgd for these 83 parks, but there will also be additional water left, which can be used to

create artificial lakes, water golf courses and even party lawns too. This can also be put to use in construction projects," an official, part of the meeting, said.

NGT had in January 2021 directed authorities in Delhi to seal all borewells in parks having an STP within a 5-km radius of it, to prevent wastage of fresh water.

It had directed agencies to instead rely on STP water for horticulture purposes.

MCD notice for feedback on layout of 3 illegal colonies

HT Correspondent

letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Municipal Corporation of Delhi has issued a fresh public notice inviting feedback and suggestions for the draft layout plans of three unauthorised (UA) colonies — Khirki Extension, Swaroop Nagar and East Azad Nagar — which will act as model pilot projects for the regularisation of around 1,800 UA colonies in the city.

The road network plans can be accessed on the MCD website (<https://mcdonline.nic.in/>) and the residents of these colonies as well as the general public can now submit their responses by February 24. "The suggestions and objections on draft Road Network Plans (RNP) of Khirki extension (Malviya Nagar), Swaroop Nagar extension (Libaspur) and East Azad Nagar as prepared by DDA are available to the general public and open for suggestions and

objections," the notice said.

People can submit their feedback via email to sgst.eastazadnagr@mcd.nic.in; sgst.kdkextn@mcd.nic.in and swrp.ngr@mcd.nic.in, respectively, for the three areas.

An MCD official, asking not to be named, said that the road network plans will be the first step in regularising approximately 1,800 unauthorised colonies in Delhi. The draft plans for the regularisation of the three colonies have been prepared with the help of the School of Planning and Architecture (SPA).

According to the officials, the plan broadly proposes a road widening exercise in these colonies under three categories of road — 6m, 9m, and 12m. "The roads have been proposed to be of 6m, 9m and 12m categories and private plot owners will have to provide space for the road widening exercise in their areas, paving the way for regu-

larisation," the official said.

The proposed road network plan specifies the colony's boundaries, existing roads, proposed roads by widening and augmentation, and residential areas, along with existing government schools, Delhi Jal Board facilities and a police station.

"Every property in the colony has been marked under the road network plan. The number of plots and extent to which they will be affected by road widening has also been specified," the official said. Unauthorised colonies are unplanned residential settlements built in violation of zoning regulations — either in contravention of Delhi's master plans or on illegally subdivided agricultural land. According to 2088 DDA regulations, RWAs should provide land for common amenities such as parks and schools, but there has been clear reluctance on the part of residents to free up this land.

4

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । सोमवार, 29 जनवरी 2024

शाहबाद दौलतपुर। रमेश नगर। लक्ष्मी नगर। लाजवंती गार्डन। जहांगीरपुरी।

समस्याएं जानने गांवों में पहुंचे DM, लोगों से मिले



अधिकारियों ने संबंधित विभागों को दिए निर्देश

■ विस/एनबीटी न्यूज, नई दिल्ली: गांवों की समस्याओं को जानने के लिए चलाए जा रहे ग्रामोदय अभियान के तहत बरदपुर खादर गांव में डीएम समेत आला अफसर पहुंचे। नाथ इंस्टिट्यूट के डीएम विक्रम सिंह, एडीएम सुभाकर घोष और एसडीएम करावल नगर संजय सोधी ने लोगों की समस्याएं सुनीं।

डीएम ने एमसीडी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी, वन विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, दिल्ली जल बोर्ड, खंड विकास अधिकारी और अन्य राजस्व के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ सबसे पहले लोगों की समस्याएं सुनीं। डीएम ने बताया कि बातचीत के दौरान ग्रामीणों ने आगनवाड़ी की स्थापना, स्ट्रीट लाइट्स, सड़कों को मरम्मत, कॉटर आरओ प्लांट, पंचायत घर की मरम्मत, चूड़ावस्था-विकलांगता-विधवा पेंशन और राशन कार्ड के लिए विशेष कैंप लगाने समेत कई मांगें रखीं।

वहीं, आउटर दिल्ली में डीएम नाथ यश चौधरी की अध्यक्षता में बवाना गांव के पुराने एमसीडी स्कूल में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बवाना में आदर्श मूल ग्रामीण पंचायत महासंघ के अध्यक्ष दयानंद कस्त ने फिरनी रोड, निकासी, तालाबों की बहाली की समस्याएं बताईं। डीएम नाथ वेस्ट अंकिता आनंद के साथ बदनपुर गांव में संसद हंसराज हंस, SDM मनीष वर्मा, सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने तालाब के सौदर्यीकरण, रमशान भूमि, स्टेडियम, सामुदायिक भवन, चौपाल, डिस्पेंसरी, करावाला से मुंडका रोड और मुंडका अंडरपास से बदनपुर डबारा ट्रेन को चौड़ा करने की मांग की।

■ बरदपुर खादर, बवाना, मदनपुर गांव में पहुंचे सीनियर अफसर ■ अधिकारियों ने गांवों का दौरा भी किया, ग्रामीणों ने बताई समस्याएं

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----- THE INDIAN EXPRESS, MONDAY, JANUARY 29, 2024 -----

Power, sewage, schools: Residents air their woes as DMs, other officials spend weekend at Delhi's villages

UPASIKASINGHAL
NEW DELHI, JANUARY 28

FROM GARBAGE disposal and choked drain to lack of medical and education facilities: This weekend gave residents of villages across 11 districts of the capital a chance to narrate their woes directly to senior officials, including the District Magistrates.

The exercise was part of Delhi Development Authority's (DDA) Dilli Gramodaya Abhiyan under which officials, including Senior Nodal Officers, DMs, and representatives from key departments such as the DDA, Municipal Corporation of Delhi (MCD), Delhi Jal Board (DJB), and Public Works Department (PWD), stayed overnight at designated villages on January 27 and 28.

The purpose of the visit was to foster direct engagement with villagers and gather insights.

On January 2, Lieutenant Governor (L-G) V K Saxena, following a Samvaad session at Raj Niwas with delegates from 180



Visits were part of Dilli Gramodaya initiative. *Gajendra Yadav*

villages, had announced that DMs would spend nights in villages within their respective districts. Following this, on January 7, all 11 DMs had stayed overnight at a few villages.

On Friday, government officials visited 11 villages, including Madanpur Dabas, Neelwal, Dallupura, Burari, Aali, and Rangpuri. The stay comprised site inspections to areas that need renovation along with open dis-

cussion with villagers and village leaders on civic issues. The officials also visited villages situated close to the designated ones, sources said.

In Dallupura, the biggest problem raised by residents was drains overflowing due to the PWD pipes being choked with garbage. "Whether it rains or not, the streets are sometimes ankle-deep in drain water. All the shop owners' have to keep a spare

wiper at hand to constantly push the water back into the open drains," said Dharmendar Kumar (45), a hardware shop owner in Pratap Chowk, Dallupura.

For Binni Kumar (39), whose family has lived in Dallupura village for generations, the chronic issue of sewage has become a source of embarrassment. "We have complained multiple times to the MCD and the PWD to clean our streets but our complaints fall on deaf ears. Now, we choose to keep our drains and streets clean ourselves. We have no other choice, we can't keep it that way when our friends and family come to visit," Kumar said.

In Aali village, the biggest worry for the residents were the narrow streets obstructing movement, and the lack of medical and school facilities. "During emergencies, the patient has to be taken to the main road, situated a kilometre away, before they can be put in an ambulance. This is because our roads are so narrow that cars cannot turn back around once they enter the lanes," said

Adil Ali (38), a resident. While the village has a primary school, the residents also expressed the desire to have a senior secondary school close by the village. They also put forth the demand of having a government dispensary.

During the Samvaad in Aali, South East DM Santosh Kumar Rai said he would look into land options for the school from the DDA and will also inform the Education Directorate about the issue. In Dallupura, MCD councillor Munesh Dedha said all the works shall begin by the first week of February and be completed by the end of the month.

In Burari, North East Delhi MP Manoj Tiwari attended the Samvaad Sunday. Here too, the residents talked about sewage and drainage issues.

Tiwari also highlighted the issue of residents not being able to get new electricity connections due to DDA's land-pooling policy which requires residents to get an NOC from the authority while applying for a new connection.

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
MONDAY, JANUARY 29, 2024

Yamuna panel wants 83 parks linked to STPs

Priyangi Agarwal
@timesgroup.com

New Delhi: The high-level committee (HLC) for rejuvenation of the Yamuna has asked Delhi Pollution Control Committee to prepare a network plan in consultation with Delhi Jal Board and Delhi Development Authority to connect 83 parks to sewage treatment plants (STPs).

DDA had earlier informed the HLC that these 83 parks have no source of water, except borewells.

According to the latest meeting of the HLC, out of 565 million gallons per day (MGD) of treated STP water, 125 MGD is used for horticulture and lake rejuvenation and water bo-



Out of 565 million gallons per day (MGD) of treated STP water, 125 MGD is used for horticulture and lake rejuvenation and water bodies

dies, and 267 MGD is the mandatory return flow in the Yamuna. The committee had earlier proposed utilising 100 MGD for groundwater rechar-

ge the DJB marshy land near the Coronation Pillar, Bhalswa lake and Jahangirpuri drain by March this year. However, there is a gap of 78 MGD of

unused treated water.

Officials said they are preparing a plan to maximise the use of treated STP water in various ways, including artificial lakes, horticulture, parks, golf courses and party lawns and explore the possibility of mandatory use in big construction projects in Delhi after further treatment.

During the eighth HLC meeting on January 10, the matter of DDA's 83 parks was taken up. It was decided during the meeting that Geospatial Delhi Limited (GSDL) will work out the distance of each of the 83 parks from the nearest STP of DJB.

"DJB will provide a list along with a brief status of survey conducted by DJB for use of trea-

ted water from STPs in 83 parks of DDA. Maps prepared by GSDL, indicating the locations of STPs and 83 DDA Parks along with length of piped network, are required for each park from the nearest STP," according to the presentation of the HLC which was recently shared.

Of the 83 parks, 65 are within a 5-km range from STPs while the remaining are over 5 km away. In the meeting, it was found that STP lines have been laid to connect 19 parks, nine parks are already covered in matters related to National Green Tribunal and four were covered in the existing proposal at Vasant Kunj. However, laying of pipelines in 16 parks is subject to permission from NHAI, railway and Delhi Metro Rail Corporation.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI
JANUARY 28, 2024

TIMES CITY

Get Set, Go! Sports Complexes In Dwarka To Be Ready By April

LG Asks DDA To Expedite Work, Sets June Deadline For Aquatics Centre

Atul.Mathur@timesgroup.com

New Delhi: Aquatics, lawn tennis, wrestling, judo, football, hockey and golf – the Dwarka sub-city will soon have a host of facilities for these sports and a few others in the next few months.

Reviewing the upcoming sports complexes in Dwarka earlier this week, lieutenant governor VK Saxena asked Delhi Development Authority to complete the civil construction work at the earliest and start the operations. The LG also directed DDA to explore the possibility of roping in private players to operate and maintain the existing sports infrastructure to ensure the members get the best possible facilities.

In the next 3-4 months, Dwarka will have a golf course ready in Sector-24 and centres of excellence for wrestling, judo, karate and kabaddi in Sector-8, for lawn tennis in Sector-19, for football and hockey in Sector-23 and for aquatics in Sector-33.

A Raj Niwas official said most sports complexes are nearing completion and the LG directed DDA to open them at the earliest. "The LG has given fresh deadlines to the DDA to complete the work," the official said.

"The deadline to complete the construction of the sports complexes in Sector-8 and Sector-23 was April 30. But the LG has directed DDA to make them ready by Feb 29 and March 31, respectively," the official added.

Similarly, the golf course in Sector-24, which is spread over 158-acre area, was to be completed by June 30 but the LG has directed the officials to complete it by March 31, while the construction of the club house, resting huts and swimming pool can be completed by April 30.



UPCOMING SPORTS FACILITIES IN DWARKA

SPORTS COMPLEX, SECTOR-8

Centre of Excellence for Wrestling, Judo, Karate and Kabaddi

Area | 9.5 hectares

Cost | ₹66.8 crore

Progress | 92%

Deadline | Feb 29, 2024



SPORTS COMPLEX, SECTOR-19

Centre of Excellence for Lawn Tennis

Area | 8.1 hectares

Project Cost | ₹81.8 crore

Progress | 90%

Deadline | April 30, 2024



GOLF COURSE, SECTOR-24

Area | 80.9 hectares

Cost | ₹78.4 crore

Progress | 80%

Deadline | March 31, 2024

SPORTS COMPLEX, SECTOR-23

Centre of Excellence for Football and Hockey

Area | 7.9 hectare

Cost | ₹39.7 crore

Progress | 88%

Deadline | Mar 31, 2024



SPORTS COMPLEX, SECTOR-33

Centre of Excellence for Aquatics

Area | 9.2 hectares

Cost | ₹109.5 crore

Progress | 50%

Deadline* | June 30, 2024

*Except for swimming pool



DDA's existing sports facilities



- 1 Sports Complex, Dwarka Sector-11
- 2 Yamuna Sports Complex
- 3 Chilla Sports Complex
- 4 CWG Village Sports Complex
- 5 Poorvi Dilli Khel Parisar, Dilshad Garden
- 6 Pitampura Sports Complex
- 7 Major Dhyani Chand Sports Complex, Ashok Vihar
- 8 Sports Complex, Rohini Sector-14
- 9 Saket Sports Complex
- 10 Siri Fort Sports Complex
- 11 Netaji Subhash Sports Complex, Jasola
- 12 Vasant Kunj Sports Complex
- 13 Baba Ganganath Sports Complex, Munirka
- 14 Hari Nagar Sports Complex
- 15 Paschim Vihar Sports Complex
- 16 Bhalswa Golf Course
- 17 Qutub Golf Course, Lado Sarai
- 18 Football ground at Sukhdev Vihar
- 19 Swimming pool and gym at Pratap Nagar



"DDA recently auctioned the high-end and ready-to-move-in flats and penthouses facing the golf-course to people. While people will soon start moving in these apartments, the LG questioned why the golf course cannot be completed by then," said another official.

Each sports complex will

have the infrastructure for a number of indoor and outdoor sports apart from other amenities such as jogging tracks, rest rooms and parking facilities. With India staking claim for organising various international sports competitions, the LG remarked that these complexes of

international standards can easily be used for training and practise purposes by both Indian and foreign squads.

Officials said the LG has also asked DDA to submit a report within 10 days if the existing sports complexes can be handed over to private players having the expertise in run-

ning such facilities for better operation and maintenance of infrastructure. "The LG has made it clear that the private players should be able to improve the amenities, maintain the equipment and train people without putting much burden on users," said an official, privy to the discussion.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

LIBRARY

PRESS CLIPPING SERVICE

the pioneer

NAME OF NEWSPAPER: SATURDAY | JANUARY 27, 2024

DATE: _____

दैनिक भास्कर
नई दिल्ली
शुक्रवार 26 जनवरी, 2024

Sustained efforts being made to develop Delhi into global city: LG

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Delhi Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena, in his Republic Day speech, on Friday said the central and the local governments are making sustained efforts to develop Delhi into a global and inclusive city. Saxena highlighted various achievements of Delhi, including in the fields of public transport, health, power sector and ration supply, in his speech.

In the last few years, Delhi has made significant progress in the power sector, he said. "The

demand for power is being met without any load shedding." The LG also lauded various agencies including Delhi Development Authority (DDA), Public Works Department (PWD), New Delhi Municipal Council (NDMC), Municipal Corporation of Delhi (MCD), Delhi Police among others, workers and employees and people of

Delhi-NCR for readying Delhi to successfully host the G-20 Summit.

The government is committed to giving top priority to health services and making them available to the people, Saxena said. "Delhi has modernised its public transport system. I am proud to inform you that by 2025, 85 per cent of the public transport buses will be electric in Delhi. That is a big achievement on the global level," he said.

The Centre has extended special financial assistance under the FAME (Faster Adoption

and Manufacturing of Electric Vehicles) scheme, he said. Efforts are being made for all the sections of society aiming for inclusive development and 72 lakh beneficiaries have received subsidised foodgrains from fair-price shops, the LG said.

"The number of 'One Nation, One Ration Card' beneficiaries is the highest (in the country)," he said. The government is also committed to tackling air and water pollution and conservation of the Yamuna river, Saxena said.

रेहड़ी पटरी की समस्या से निपटने 3 एजेंसियां नियुक्त, जल्द होगा सर्वे

नई दिल्ली | मेयर शैली ओबेरॉय ने गुरुवार को कहा कि आने वाले एक दो सालों में रेहड़ी पटरी की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। टाउन वैंडिंग कमेटी बनने के बाद रेहड़ी वालों को सर्टिफिकेट ऑफ वैंडिंग दिया जाएगा। साथ ही जगह-जगह रेहड़ी पटरी लगाने की समस्या के हल के लिए उनके लिए अधिकृत अड्डे बनाए जाएंगे जहां वो रेहड़ी लगा सकेंगे। मेयर ने विश्वास नगर विधानसभा में जर्जर हालत में पड़े सार्वजनिक शौचालय की मरम्मत और साफ सफाई के निर्देश दिए। इसके अलावा मेयर ओबेरॉय ने गंदगी से पटी पड़ी दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की जमीन को भी साफ करने के निर्देश दिए।

केंद्र व राज्य सरकार मिलकर दिल्ली के विकास के लिए कर रहे काम : एलजी

ATED-----

नई दिल्ली (एसएनबी)। गणतंत्र दिवस पर उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शुक्रवार को दिल्लीवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार समन्वय के साथ राष्ट्रीय राजधानी को एक वैश्विक और समावेशी शहर के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने जी-20 शिखर सम्मेलन की सफलता का जिक्र करते हुए दिल्ली ने सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य, बिजली क्षेत्र और राशन आपूर्ति के क्षेत्र में प्रगति की है। संविधान के निर्माताओं, देश की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

उन्होंने कहा कि स्थानीय सरकार बुनियादी क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रही है। बिजली क्षेत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में काफी प्रगति की है और बगैर किसी रोक के निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली पुलिस

समेत सभी एजेंसियों, श्रमिकों, कर्मचारियों एवं दिल्ली-एनसीआर के लोगों की सराहना की। एलजी ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने हुए उन्हें लोगों तक उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली ने अपनी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का आधुनिकीकरण किया है। मुझे यह बताते

■ सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य, बिजली क्षेत्र एवं पुलिस प्रणाली में व्यापक सुधार

■ डीडीए, एमसीडी, एनडीएमसी एवं पीडब्ल्यूडी के प्रयासों की सराहना

हुए गर्व हो रहा है कि 2025 तक दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन में 85 फीसद हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक बसों की होगी। वैश्विक स्तर पर यह बड़ी उपलब्धि है। उप-राज्यपाल के कहा कि केंद्र ने फास्टर एडॉप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम) योजना के तहत विशेष वित्तीय सहायता दी है। समावेशी

विकास के लक्ष्य के साथ समाज के सभी वर्गों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और 72 लाख लाभार्थियों को उचित मूल्य की दुकानों से रिहायती दर पर खाद्यान्न मुहैया कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार वायु और जल प्रदूषण से निपटने के लिए यमुना नदी के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली नगर निगम भी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों के प्रभावी और समय पर कार्यान्वयन के लिए प्रयास कर रहा है। बीते एक साल में दिल्ली को बदलने के लिए कई परियोजनाएं पूरी की गई हैं। दो विश्व स्तरीय सभागारों, भारत मंडपम और यशोभूमि का उद्घाटन किया गया है। मेरठ तथा दिल्ली के बीच रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) शुरू हो चुकी है। दिल्ली-अलवर एवं दिल्ली-पानीपत कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है। दिल्ली पुलिस में लगातार हो रहे सुधार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं पर होने वाले अपराधों पर नियंत्रण को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस प्रणाली का तेजी से डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है।

गांवों में डीएम रात्रिवास कर तैयार करेंगे विकास का खाका

नई दिल्ली (एसएनबी)। उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजधानी के ग्रामीण विकास पर फोकस करते हुए दिल्ली ग्रामोद्योग अभियान का दूसरा चरण शुरू करने का निर्णय लिया है। यह अभियान 27 से 28 जनवरी तक चलेगा। इसमें 11 गांवों को शामिल किया गया है। उप-राज्यपाल ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह दो दिन तक लगातार गांव वालों के बीच रहकर संवाद स्थापित करेंगे और वहीं रात्रिवास करेंगे। जिलाधिकारी विकास का खाका तैयार करेंगे और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) उसे लागू करेगा। दिल्ली ग्रामोद्योग अभियान का पहला चरण 7 एवं 8 जनवरी को हुआ था।

■ दिल्ली ग्रामोद्योग अभियान का दूसरा चरण 27 से

■ 11 गांवों में डीएम करेंगे ग्रामीणों के साथ संवाद

प्राथमिकता देने की जरूरत है। संवाद के दौरान डीडीए, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी समेत अन्य विभागों के अधिकारी भी मौके पर रहेंगे। उप-राज्यपालने जिलाधिकारियों से कहा है कि अभियान के बाद रिपोर्ट तैयार कर उन्हें सौंपी जाए।

अभियान के तहत जिलाधिकारी सुबह निर्धारित गांव में पहुंचेंगे और करीब एक घंटे विजिट करेंगे और बाद में संवाद करेंगे। दोपहर बाद सभी अधिकारी गांवों की विशिष्ट साइट पर जाकर निरीक्षण करेंगे और जगह को चिन्हित करेंगे। शाम को 6 से 7 बजे के बीच गांव वालों के साथ चर्चा करेंगे और उनकी समस्याएं सुनकर उनसे फीडबैक लेंगे और उनका समाधान निकालेंगे। दूसरे दिन 28 जनवरी को अधिकारी ग्रामीणों से सलाह लेंगे और दूसरे चरण का संवाद करेंगे। शाम को 7 से 11 बजे के बीच संप्रभावित रोडमैप तैयार करेंगे। इस अभियान की शुरुआत उप-राज्यपाल ने नए साल पर 2 जनवरी को राजनिवास में ग्रामीणों की बैठक बुलाकर की थी। इसमें 180 गांवों के 500 प्रतिनिधि शामिल हुए और उन्होंने अपने सुझाव दिए थे।

राजनिवास के जारी बयान में बताया है कि दिल्ली ग्रामोद्योग अभियान के इस चरण में नीलवाला, मदनपुर डबास, छावला, भाटी, आली, दल्लूपुर, सबोती, बदरपुर खादर, बुराड़ी, रंगपुरी और मुंगेशपुर को शामिल किया गया है। जिलाधिकारी अपने जिले के गांव में जाकर ग्रामीणों से संवाद करेंगे। संवाद में तय करेंगे कि वहां किस तरह के विकास को

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----- THE HINDU Saturday, January 27, 2024
DELHI

Efforts of govts. making city world-class, inclusive: L-G

In his Republic Day address, Lieutenant-Governor lists various development works undertaken in 2023 when G-20 Summit took place in the Capital; steers clear of mentioning AAP government

The Hindu Bureau
NEW DELHI

Lieutenant-Governor Vinai Kumar Saxena, in his Republic Day address on Friday, highlighted the development work undertaken by government agencies in the last year and said that many infrastructure projects are changing the face of the national capital.

"To make Delhi a world-class and inclusive city, our Central and local governments are making continuous efforts," said Mr. Saxena, while refraining from mentioning the Aam Aadmi Party government in Delhi.

Mr. Saxena, in his televised address, said that 2023 was extremely important for both the nation and the city as they hosted the G-20 Summit for the first time. "I congratulate the DDA, PWD, NDMC,



Walking tall: The Delhi Police contingent marching down Kartavya Path on the occasion of the 75th Republic Day. SHIV KUMAR PUSHPAKAR

MCD, Cantonment Board, Delhi Police, CPWD, NHAI, and the Indian Air Force for this success and the thousands of personnel and workers who worked day and night. I also thank all the people in Delhi-NCR," the L-G added.

Lauds infra push
Talking about the Central infrastructure projects undertaken, he added, "Two world-class convention

centres were launched in the Capital in the form of Bharat Mandapam and Yashobhoomi. Similarly, the RRTS [Regional Rapid Transit System] line has started between Delhi and Meerut."

Mr. Saxena also said that Delhi has modernised its public transport system to suit the needs of the residents. "I am very proud to say that by 2025, 80% of Delhi's buses will be elec-

tric, which will be a big achievement at the global level."

He also lauded Delhi Police for utilising technology for the effective enforcement of law and order.

"Adoption of multi-pronged strategies, crime mapping and identification of hotspots, deployment of personnel on roads and patrolling was ensured [by the police]," Mr. Saxena said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

पंजाब केसरी
DELHI

27 जनवरी, 2024 PAPERS

DATED

एलजी सक्सेना की 'संवाद' मुहिम के जरिए शासन में हुई लोगों की भागीदारी सुनिश्चित

एलजी के निर्देश पर गांवों में रात गुजारेंगे डीएम

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा संवाद के जरिए शासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शुरु की अनूठी पहल का सिलसिला लगातार जारी है। इस पहल में विशेष रूप से ग्रामीणों से विचार कर दिल्ली के गांवों के विकास की योजना तैयार करना और उन्हें कार्यान्वित करना शामिल है। राजनिवास के अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीणों के साथ संवाद के माध्यम से अनुभव प्राप्त करने के लिए डीएम द्वारा गांवों में रात भर रुकने की कवायद लगातार जारी है। इस कड़ी में वरिष्ठ नोडल अधिकारी, डीएम और डीडीए, एमसीडी, जलबोर्ड और पीडब्ल्यूडी आदि जैसे संबंधित एजेंसियों विभागों के सभी वरिष्ठ अधिकारी आगामी सप्ताहांत 27 और 28 जनवरी को राजधानी के सभी 11 जिलों के चिन्हित गांवों में रात बिताएंगे।

पहले दिन सभी डीएम सुबह 11 बजे तीन घंटे तक चयनित गांव और

ख़ास बातें...



■ ग्रामीणों के साथ करेंगे गांवों के विकास पर चर्चा, बनाएंगे विकास की योजना

उसके आस पास के गांवों के लोगों से संवाद करेंगे। दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक वे विभिन्न संबंधित विभागों डीडीए, राजस्व, जलबोर्ड और एमसीडी आदि के सभी संबंधित अधिकारियों के साथ पिछले 'संवाद' के दौरान पहचाने गये कार्यों के अनुसार निरीक्षण के लिए

11 जिलों के चयनित गांव

1. पश्चिम - नीलवाल
2. उत्तर-पश्चिम - मदनपुर डबास
3. दक्षिण-पश्चिम - छावला
4. दक्षिण-भाटी
5. दक्षिण-पूर्व - आली
6. पूर्व - दल्लूपुरा
7. शाहदरा - सबौली
8. उत्तर पूर्व - बदरपुर खादर
9. सेंट्रल - बुराड़ी
10. नई दिल्ली - रंगपुरी
11. उत्तर - मुंगेशपुर

महत्वपूर्ण स्थलों का दौरा करेंगे। शाम 6:00 बजे से 7:00 बजे तक सभी ग्रामीणों के साथ नाइट फायर पर एक चर्चा आयोजित की जाएगी, जहां ग्रामीण अपनी शिकायतें और प्रतिक्रिया डीएम के साथ साझा करेंगे। वहीं 27 जनवरी 2024 और 28 जनवरी 2024 के बीच की मध्यरात्रि

के विश्राम के बाद वे चिन्हित गांव के विभिन्न स्थानों पर विकास के लिए अस्थायी रोडमैप साझा करने के लिए सुबह 7:00 बजे से 11:00 बजे के बीच 'संवाद' का दूसरा दौर शुरू करेंगे। यहां बता दें कि एलजी द्वारा 2 जनवरी 2024 को आयोजित संवाद @राजनिवास आयोजित किया गया था। जिसमें दिल्ली के 180 गांवों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस दौरान एलजी ने सभी संबंधित डीएम रातभर गांव में रुके थे, सभी 11 डीएम अपने जिले के चयनित गांव में 7 जनवरी 2024 को सुबह पहुंच गए थे और 8 जनवरी 2024 की सुबह तक गांव में ही रुके थे। उस दौरान ग्रामीणों के फीडबैक से मिले अनुभव से अधिकारियों को दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत किए जाने वाले विशिष्ट कार्यक्रमों को तैयार करने में मदद मिली। इसकी सफलता से उत्साहित होकर अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच यह दूसरा संवाद होगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

29 जनवरी • 2024

राष्ट्रीय
सहारा ERS

DATED

सर्किल रेट नहीं बढ़ा तो होगा आंदोलन : सोलंकी

नई दिल्ली (एसएनबी)। बवाना में 360 गांव की पंचायत हुई। इस दौरान पालम के प्रधान चौधरी सुरेन्द्र सोलंकी ने कहा कि सरकारें दिल्ली देहात की अनदेखी करना बंद करें। हमारी पुरानी मांगों पर जल्द संज्ञान लेकर हमारा समाधान करें। मुआवजा राशि बढ़ाकर कम से कम पांच करोड़ रुपए एकड़ जल्द किया जाए।

दिल्ली देश की राजधानी है, जहां के किसानों के साथ अब अन्याय और बर्दाशत नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि

■ एक सप्ताह का दिया अल्टीमेट

अगर एक सप्ताह के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो दिल्ली के किसान एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसका खामियाजा सरकारों को भुगतना पड़ेगा। पंचायत में बवाना के प्रधान चौधरी धारा सिंह, लाडो सराय 96 के चौधरी खजान सिंह प्रधान बांसा 12, प्रधान चौधरी नरेश, सुरेहड़ा 17 से राव त्रिभावन, नरेला 17 प्रधान रणबीर सिंह, समुंदर सिंह प्रधान कराला 17, राजपाल सिंह प्रधान पल्ला 12, रूपचंद प्रधान बख्तावरपुर 12, सुरेश प्रधान नांगलोई 9 आदि मौजूद थे।

चौधरी सुरेन्द्र सोलंकी ने कहा कि हमने लगभग चार माह पूर्व भी ग्यारह सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन किया था। इसमें मुआवजा

राशि बढ़ाने का भी मुद्दा था, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इस फ़ाइल को जल्द उपराज्यपाल के पास भेजे। उपराज्यपाल इस पर हस्ताक्षर करके दिल्ली के किसानों को बड़ी राहत दें।

उन्होंने कहा कि दारिद्र्य खारिज को भी जल्द खोला जाए। भूमि एक्ट की धारा-81 और धारा-33 के तहत कार्यवाही को समाप्त किया जाए, धारा-81 में दर्ज पुराने

मामलों को तुरन्त वापस लिया जाए। धारा-74 (4) के तहत गांवों के भूमिहीनों, पूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं आदि को ग्रामसभा की भूमि में आवंटित रिहायशी व कृषि भूमि के पट्टों को मालिकाना हक दिया जाए। ग्रामसभा की जमीन का डीडीए को हस्तान्तरण करने पर रोक लगाई जाए, सभी गांवों में लाल डोरे का विस्तार किया जाए आदि मांगें हैं। श्री सोलंकी ने कहा कि पंचायत में निर्णय लिया गया कि सात लोकसभा में से पांच पर दिल्ली के मूल निवासियों में से उतारा जाए। सभी पार्टियों से पंचायत आग्रह करती है कि दिल्ली के मूल निवासियों को तरजीह देने का काम करे।

दैनिक भास्कर

नई दिल्ली, रविवार 28 जनवरी, 2024

सरकारी जमीन खाली करने के लिए आदेश

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

दिल्ली के लाडोसराय इलाके में सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर उस पर झुगियां बना डेयरी और कबाड़ी का काम कर रहे हैं। जमीन डीडीए के अंतर्गत आती है। एनजीटी ने सौरभ सेजवाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए डीडीए को जमीन खाली करवाने का आदेश दिया है। एनजीटी ने डीडीए को यह जमीन खाली कराने के लिए तीन महीने का समय दिया है। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने एक्शन लेने के लिए कहा और जमीन खाली कराने के लिए कहा।